बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 191 ● नई दिल्ली ● बुधवार 30 जुलाई 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

क्रिकेट नहीं पीओके चाहिए! प्रमोद तिवारी बोले, गोली और गोला एक साथ नहीं चल सकते

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मंगलवार को सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान संघर्ष विराम समझौते के लिए कौन जिम्मेदार था और किन परिस्थितियों में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटक मारे गए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बावजूद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट संबंध क्यों जारी हैं। उन्होंने कहा कि गोली और गेंद एक साथ नहीं चल सकते। एएनआई से बात करते हुए, तिवारी ने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से कहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर या संसद में किसी भी अन्य मुद्दे को लेकर कांग्रेस में कोई विरोधाभास नहीं है। हमारी बात स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जवाब देना चाहिए कि संघर्ष विराम के लिए कौन जिम्मेदार था।

दिल्ली में आफत वाली बारिशः जलभराव के बाद लगा जाम, आतिशी ने रेखा सरकार को घेरा; एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली।

दिल्ली समेत एनसीआर में मंगलवार सुबह से ही बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। जलभराव होने की वजह से ट्रैफिक जाम लग गया है। बीती रात से ही रुक-रुक कर बारिश हो रही है। वहीं बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जबकि पूर्व सीएम आतिशी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल पूछा है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने बारिश के बीच हो रहे जलभराव पर दिल्ली सरकार को घेरा है। एक्स पर पोस्ट साझा कर आतिशी ने लिखा कि प्रगति मैदान के सामने वाली सड़क का हाल देखिए... 10 मिनट की बरसात हुई और दिल्ली पानी पानी हो गई। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आगे लिखा कि ये 4 इंजन वाली कमाल की सरकार है। पूछा कि कहां हैं दिल्ली के पीडब्लूडी मंत्री प्रवेश वर्मा और क्या कर रही हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह हुई भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण इंडिगो, स्पाइसजेट और एयर इंडिया जैसी प्रमुख एयरलाइनों ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। उड़ान संचालन में संभावित व्यवधान की चेतावनी दी गई है। भारी बारिश की वजह से कई उड़ानों पर असर पड़ा है। दिल्ली के अलग-अलग अस्पतालों में पानी भर गया। जिसकी वजह से कई मरीजों को काफी परेशानी हुई। सफदरजंग, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल सहित अन्य अस्पताल में आज तेज बारिश की वजह से पानी भर गया। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट साझा कर लिखा कि अब क्या

कहेंगे। मंगलवार सुबह जैसे ही लोगों ने आंखें खोलीं, चारों ओर एक सुहावना और ठंडक भरा मौसम दिखाई दिया। आसमान से बादल झूम-झूमकर बरसे, लेकिन इस खुशनुमा बारिश ने लोगों को राहत के साथ-साथ मुश्किलें भी दीं। शहर के कई इलाकों में जलभराव ने राहों को रोकने की कोशिश की, मगर मंजिल की चाह में लोग भीगते हुए भी अपने-अपने सफर पर निकल पड़े। मध्य दिल्ली के पटेल नगर इलाके में हुए जलभराव में से बचते-बचाते लोग निकलते दिखे। सोमवार को भी सुबह से ही बादल और सूरज के बीच अठखेलियों का खेल जारी रहा। दिन के समय कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन इसने और उमस भरी गर्मी बढ़ा दी।

इस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस अधिक के साथ 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक के साथ 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते 24 घंटे में हवा में नमी का 84 से 64 फीसदी रहा। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार शाम 5:30 बजे तक पालम में 10.7, आया नगर में 0.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। विभाग के अनुसार, बुधवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री के बीच और न्यूनतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं, बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री के बीच और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

गरज चमक के साथ बारिश की भी संभावना है। साथ ही, शुक्रवार को भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 35 और न्यूनतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इसके अलावा, शनिवार और रविवार को भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

आप ने चला ये बड़ा दांव, पूरे देश में चलाएंगे अभियान; मैदान में उतारी 3000 कार्यकर्ताओं की टीम

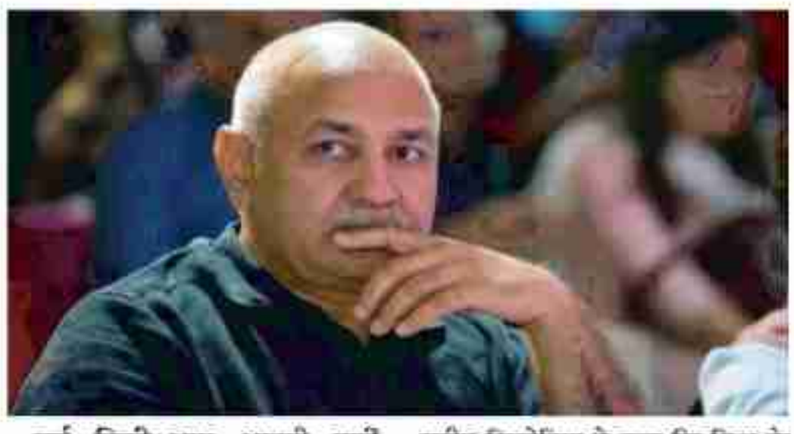

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) की प्रेस वार्ता में वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने देश की शिक्षा व्यवस्था पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। इसीलिए आप की ओर से एक शिक्षा अभियान चलाकर देशभर में संचालित जर्जर स्कूलों की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके लिए उन्होंने बताया कि तीन हजार कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

चीन, जापान और कोरिया का दिया उदाहरण

मनीष सिसोदिया ने कहा कि विश्व के कई देश जैसे जापान में पांचवीं कक्षा के बच्चों को एआई आधारित शिक्षा दी जा रही है।

चीन व कोरिया शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं लेकिन भारत में बच्चे जर्जर इमारतों और टूटी छतों वाले स्कूलों में पढ़ने को मजबूर हैं। सिसोदिया ने बताया कि दसवीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में भी एआई जैसे आधुनिक विषयों का अभाव है।

स्कूलों की दशा सुधारने की मुहिम

सिसोदिया ने घोषणा की कि आप के तीन हजार कार्यकर्ता 1 अगस्त से 7 अगस्त तक देशभर के ग्रामीण स्कूलों का दौरा करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य स्कूलों की बदहाल स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना है। कार्यकर्ता स्कूलों की इमारतों, बुनियादी सुविधाओं और शिक्षा की गुणवत्ता का जायजा लेंगे। इस रिपोर्ट को प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें।

बच्चों के भविष्य के लिए जंग

पत्रकारों से वार्ता करते हुए सिसोदिया ने जोर देकर कहा कि बच्चों का भविष्य देश का भविष्य है। टूटी छतों और असुरक्षित स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। आप का यह अभियान केवल स्कूलों की स्थिति सुधारने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन की मांग करता है। कार्यकर्ता प्रशासन के साथ मिलकर स्कूलों की मरम्मत और आधुनिकीकरण के लिए दबाव बनाएंगे। इस पहल से आप देशभर में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने और बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में काम करेगी।

रिटायर हो रहे हैं सीपी संजय अरोड़ाः कौन बनेगा दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर?, ये तीन नाम रेस में सबसे आगे

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। अभी तक यह प्रयास लगाए जा रहे थे कि गृह मंत्रालय दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को एक्सटेंशन दे सकता है। लेकिन पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के फेयरवेल की तैयारी करने का आदेश पुलिस मुख्यालय से निकाला गया है। इस आदेश के बाद पुलिस कमिश्नर के एक्सटेंशन के सभी संभावित कयासों पर विराम लग गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर पद के लिए जिन संभावित आईपीएस अधिकारियों का नाम चर्चा में है, उनमें एसबीके सिंह, प्रवीर रंजन, और सतीश गोलचा का नाम सबसे ऊपर है। दिल्ली के किंग्सवे कैंप न्यू पुलिस लाइन में पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा का फेयरवेल होगा। 31 जुलाई से पहले नए पुलिस कमिश्नर के नाम का आदेश आ सकता है। संजय अरोड़ा तमिलनाडु कैडर के 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। संजय अरोड़ा आईटीबीपी के डीजी के पद पर काम किया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने। इनसे पहले राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे। मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले संजय अरोड़ा ने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट जयपुर से की है। लोक सेवा में आने के बाद उन्होंने तमिलनाडु में कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दीं। इस दौरान डकैत वीरप्पन के गिरोह का भंडाफोड़ करने वाले स्पेशल टास्क फोर्स में भी अरोड़ा एसपी थे। उनकी टीम को मिली सफलता के लिए उन्हें सीएम गैलंट्री मेडल से सम्मानित किया गया। 1991 में संजय अरोड़ा ने एनएसजी से ट्रेनिंग ली थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसएसजी के गठन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आईटीबीपी के साथ अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 2000 से 2002 तक मसूरी में अकादमी में प्रशिक्षक भी थे। वह कोयंबटूर शहर में पुलिस के प्रमुख बने और चेन्नई में अपराध और यातायात के लिए अतिरिक्त आयुक्त भी रहे।

संसद में दरकिनार हुए मनीष तिवारी, कांग्रेस को दो टूक! जो खामोशी न समझे, वो शब्द क्या समझेंगे

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के लिए वक्ताओं की सूची से खुद को और अपने साथी सांसद शशि थरूर को बाहर रखे जाने पर अपनी पार्टी पर कटाक्ष किया। आनंदपुर साहिब से सांसद ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में एक समाचार लेख का स्क्रीनशॉट साझा किया, जिसमें वक्ताओं की सूची से उन्हें बाहर किए जाने पर प्रकाश डाला गया था। तिवारी ने 1970 की फिल्म पूरब और पश्चिम के प्रसिद्ध देशभक्ति गीत है प्रीत जहाँ की रीत सदा के बोल भी साझा किए। इसके बाद मनीष तिवारी की नाराजगी की खबरें चर्चा में है। उन्होंने मीडिया से कहा, अंग्रेजी में एक कहावत है- अगर आप मेरी खामोशी को नहीं

समझते, तो आप मेरे शब्दों को कभी नहीं समझ पाएंगे। सूत्रों ने बताया कि तिवारी चर्चा में भाग लेना चाहते थे और उन्होंने विपक्ष के नेता (राहुल गांधी) के कार्यालय को एक पत्र लिखकर बोलने की इच्छा भी जताई थी। हालाँकि, कांग्रेस ने उन्हें मैदान में उतारने का फैसला नहीं किया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस सांसद अमर सिंह को भी कांग्रेस ने बहस में बोलने के लिए नहीं चुना। थरूर के मामले में, कांग्रेस ने केरल के सांसद से चर्चा के दौरान बोलने का अनुरोध किया था।

हालाँकि, सूत्रों के अनुसार, थरूर ने यह कहते हुए निमंत्रण अस्वीकार कर दिया कि वह ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना में पार्टी लाइन का पालन नहीं कर पाएँगे। थरूर ने पार्टी नेतृत्व को बताया कि जब भी वह विदेश यात्रा पर जाते हैं, तो उनका यह विचार हमेशा से रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है और वे इस लाइन से विचलित नहीं हो सकते। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वह संसद में बोलेंगे, तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने अपनी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह मौन व्रत पर हैं।

प्रोजेक्ट्स में देरी पर सीएम रेखा गुप्ता सख्त, सचिवों को आदेश जारी कर दिए ये निर्देश

नई दिल्ली। विभिन्न परियोजनाओं के बीच आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अब स्वयं ऐसे मामलों को देखेंगी और कार्रवाई करेंगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों और प्रधान सचिवों को आदेश जारी कर हर महीने की परियोजनाओं से संबंधित रिपोर्ट देने के लिए निर्देश दिए हैं। इसे शासन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के एंगल से भी देखा जा रहा है। परियोजनाओं में आ रही बाधाओं से संबंधित चर्चाओं और फैसले के लिए हर माह के अंतिम दिवस पर सभी मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। इससे पहले अप्रैल में भी सीएम कार्यालय इस तरह के निर्देश दे चुका है जिस कार्रवाई भी हो रही है अब इसे और विस्तार दिया जाएगा। सरकार से जुड़े जानकारों की मानें तो इससे महत्वपूर्ण परियोजनाओं की निगरानी बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री हर सोमवार को अपने मंत्रियों के साथ विभिन्न कार्यों की प्रगति पर चर्चा करने के लिए समीक्षा बैठकें करती हैं। नया आदेश निगरानी तंत्र को एक कदम आगे ले जाता है। नए आदेश के तहत हर महीने की 29 तारीख से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाने वाली मासिक रिपोर्ट में विभाग के कार्यक्रमों, योजनाओं और उपलब्धियों का विवरण होगा ताकि प्रगति का आकलन किया जा सके। इसमें उन बाधाओं का अलग से जिक्र होगा जिनके कारण परियोजना के काम में कोई अड़चन आ रही है। ऐसी समस्याओं को अभी तक दूर किए जाने वाले प्रयासों का जिक्र भी होगा। विभाग प्रमुखों को अपनी रिपोर्ट में यह भी बताना होगा कि क्या किसी विशेष योजना या परियोजना के लिए अंतर-विभागीय समन्वय की आवश्यकता है और देरी या रुकावट पैदा करने वाले आंतरिक और बाहरी दोनों कारकों का विवरण भी देना होगा।

जब व्यापार बंद, पानी रोका तो पाकिस्तान से क्रिकेट क्यों?-ओवैसी

नई दिल्ली। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आगामी भारत-पाकिस्तान मैच के खिलाफ विपक्ष के विरोध में शामिल हो गए हैं और पहलगाम आतंकी हमले के पांच महीने बाद होने वाले एशिया कप मैच को देखने को लेकर अपनी असहजता व्यक्त की है। तीन दिन पहले जारी एशिया कप 2025 के कार्यक्रम के अनुसार, भारत और पाकिस्तान 14 सितंबर को ग्रुप स्टेज का मैच खेलेंगे। इस मैच ने विपक्ष के विरोध को जन्म दिया है, जो आम जनता में पाकिस्तान के आतंकी गठजोड़ के कारण उसके बहिष्कार की भावना को दर्शाता है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए, ओवैसी ने कहा कि उनकी अंतरात्मा उन्हें भारत-पाकिस्तान मैच देखने की इजाज़त नहीं दे रही है। 56 वर्षीय सांसद ने कहा कि जब पाकिस्तान के विमान हमारे हवाई क्षेत्र में नहीं आ सकते, उनकी नावें हमारे जलक्षेत्र में नहीं आ सकतीं, व्यापार समाप्त हो गया है, तो आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच कैसे खेलेंगे? जब हम पानी नहीं दे रहे हैं, हम पाकिस्तान का 80 प्रतिशत पानी रोक रहे हैं, यह कहते हुए कि खून-पानी नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे। हैदराबाद के सांसद, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार की जन-पहुंच पहल का भी हिस्सा रहे हैं, ने ज़ोर देकर कहा कि मेरी अंतरात्मा मुझे वह मैच देखने की इजाज़त नहीं देती। लोकसभा में बोलते हुए उन्होंने पूछा कि क्या सरकार में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मृतकों के परिवार को बुलाकर कहे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला लिया और अब आप पाकिस्तान का मैच देखें। 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 में आठ देश हिस्सा लेंगे। ग्रुप चरण में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 14 सितंबर को होगा। दोनों टीमें सुपर 4 चरण के लिए पसंदीदा हैं और टूर्नामेंट के दौरान फिर से भिड़ सकती हैं। अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुँच जाती हैं, तो तीसरा मुकाबला भी संभव है।

भारत में बुजुर्गों का तिरस्कार कब खत्म होगा?

वैश्विक स्तरपर पूरी दुनियाँ में भारत ही एक ऐसा संस्कारी सभ्यता का प्रतीक सर्वधर्म समभाव महा मानवों का देश है जहां माता-पिता बड़े बुजुर्गों की आज्ञा को उपासकों की रज़ा व आदेश मानने वालों का यह देश आज पाश्चात्य वैचारिकता की ओर बढ़ गया है। मैं एडवोकेट किशन सम्मुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र जब तीन दिन पहले प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग माँ के परिजनों द्वारा उसे सड़क के कोने में फेंक कर भागने व 25 जुलाई 2025 को उन्हें अस्पताल में बचाने की कार्यों कोशिशों के बावजूद उसकी मृत्यु हो गई,मां को फेंक भागने का वीडियो देखकर भारत के संस्कारी लोगोंका दिल पसीज गया,मैं भी सीसीटीवी वीडियो देखकर ये पढ़,फेंकने वाले संभवत परिवार के दो महिला व एक पुरुष दिखाई दे रहे है, जो इलेक्ट्रिक ऑटो से आए थे, बुजुर्ग माँ को एक ने दोनों हाथों व दूसरे ने दोनों पैरों से पकड़कर बेड किनारे फेंक कर उनको चादर डालकर भाग गए। मेरा मानना है यह सीसीटीवी वीडियो देखकर सबका खून खौल उठा होगा। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, जो 21 अगस्त 2025 तक चलेगा। इस आर्टिकल के माध्यम से मैं केंद्र सरकार व सभी पार्टियों के सभी सदस्यों व लोकसभा सांसदों से हृदयपूर्वक मार्मिक अपील करना चाहता हूं कि, तत्काल इसी हफ्ते संसद में माता-पिता सीनियर सिटीजन (अत्याचार अपमान व दुर्व्यवहार निवारण) विधेयक 2025 बनाकर पेश करें, व सभी मिलकर लोकसभा में 543/0 व राज्यसभा में 245/0 के रिकॉर्ड तोड़ समर्थन से यह बिल पारित कर पूरे विश्व में एक उदाहरण पेश करें, तो भारत सहित पूरी दुनियाँ खुश हो जाएगी। मैं कुछ वर्षों से कहना चाहूंगा कि आज भारत भले ही युवाओं का देश है, परंतु एक रिपोर्ट के अनुसार 25 वर्षों के बाद भारत में 60 प्लस की संख्या अधिक होगी, जिसमें आज के सभी युवा शामिल होंगे। आज बुजुर्गों की स्थिति यह है कि 77 फीसदी बुजुर्गों के साथ भावनात्मक मौखिक दुर्व्यवहार, 24 फीसदी से शारीरिक दुर्व्यवहार होता है, तो 27 फीसदी आर्थिक शोषण व 50 फीसदी की उपेक्षा होती है। आज वर्तमान कानून माता-पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण (संशोधित) अधिनियम 2019 व 2007 में बनाए गए माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम नाकाफी सिद्ध हो रहे हैं,क्योंकि आज करीब 12 फीसदी बुजुर्गों को ही इन कानूनों के बारे में जानकारी है,ऐसी रिपोर्ट कहती है। मेरी अपील है कि मेरे द्वारा सुझाए गए उपरोक्त विधेयक में हत्या सामूहिक रेप व देशद्रोह की धाराओं के समतुल्य सजा का प्रावधान करना जरूरी हो गया है। अयोध्या एसपी का इंटरव्यू मैंने देखा तो पता चला पूरी तेज रफ्तार से जांच जारी है।महिला का फोटो जारी कर आरोपियों का पता बताने वालों के लिए इनाम की घोषणा की गई है। 25 किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं अनेक पुलिस टीमें बनाई गई है, परंतु मेरा मानना है,आरोपी पकड़े जाने के बाद भी कानून की खामियों से शीघ्र ही जमानत व केस ट्रायल होने के बाद पूरी तरह छूट जाने की संभावना है, जिसका संज्ञान माननीय सभी सांसदों को लेना चाहिए, व सभी दलों को भी अपने-अपने स्तर पर एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है।चूंकि रामनगरी अयोध्या में शर्मसार हुई मानवता, 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला को संभवतः परिवार वालों ने लावारिस फेंककर भागे, सीसीटीवी में कैद हुई हृदय विदारक घटना,इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, भारत में बुजुर्गों का तिरस्कार कब खत्म होगा? राम शर्मिंदा हैं,अयोध्या में संभावित परिजनों द्वारा सड़क पर माँ को फेंक भाग निकले, माँ दम तोड़ गईं। साथियों बात अगर हम 24 जुलाई 2025 को 1.50 एएम अयोध्या में हुई माँ को लावारिस फेंक भागने की घटना की करें तो,आज पूरे देश में अयोध्या की चर्चा हो रही है, लेकिन आज अयोध्या की चर्चा भगवान राम के लिए नहीं बल्कि एक बुजुर्ग महिला की वजह से हो रही है, जिसे कुछ लोगों ने अयोध्या में लावारिस छोड़ दिया और कुछ ही घंटे बाद उसकी मौत हो गई। ये घटना 23 जुलाई की देर रात 1 बजकर 50 मिनट की है। जब अयोध्या के दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज के पास रात के अंधेरे में संभवतःपरिवार वाले 80 वर्षों की इस बुजुर्ग महिला को लेकर आए और उसे सड़क किनारे फेंककर चले गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दो महिलाएं और एक पुरुष बुजुर्ग महिला को ई-रिक्शा से उठाकर वहां से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नगर) ने कहा,अब तक की जांच में पता चला है कि बुजुर्ग महिला को उसके रिश्तेदार देर रात ई-रिक्शा में लाए थे, और फिर उसे सड़क किनारे छोड़कर चले गए। सूचना मिलने के बाद, पुलिस महिला को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले गई, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। साथियों बात अगर हमसीसीटीवी कैमरों व पुलिस जांच की करें तो,सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि बुजुर्ग महिला को ई-रिक्शा में लाकर सड़क किनारे छोड़ दिया गया। ई-रिक्शा में सवार लोग उसके ऊपर कंबल डालकर तुरंत वहां से चले गए। एसपी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए दोषियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। अभी तक करीब 25 किलोमीटर का दायरा सीसीटीवी के जरिए चेक कर लिया गया है जल्द ही ई रिक्शा चालक और परिजन का पता लगा लिया जाएगा जिस इलाके में ये वारदात हुई वहां के स्थानीय लोगो का कहना है कि ये इलाका सुल्तानपुर गोंडा,बहराइच और अम्बेडकरनगर को जोड़ता है ऐसे में संभावना है कि यह लोग इन जिलो से भी आए होंगे,स्थानीय लोगों ने इस पूरे वारदात की अत्यंत कड़ी निंदा की है। साथियों बात अगर हम साथियों बात अगर हम सूचीगत जातियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 2019 के समकक्ष माता-पिता बुजुर्गों के सम्मान के लिए कानून बनाने की करें तो जिस तरह सामाजिक सौहार्दपूर्णता समानता को कायम रखने के लिए एट्रोसिटी (अमेंडेड) कानून 2019 बनाया गया है,जिसका डर हमेशा उपद्रवी लोगों में बना रहता है या फिर कभी नए फौजदारी अधिनियम 2023 में अपराध को रोकने अनेक धाराओं का डर लोगों में बना हुआ है उसी तर्ज पर मेरा सुझाव है कि संसद के 21 अगस्त 2025 तक चलने वाले मानसून सत्र में माता-पिता बुजुर्गों के साथ होने वाली क्रूरता दुष्परिणाम दुर्व्यवहार अपमान व दुत्कार पर लगाम लगाने के लिए माता-पिता वह वरिष्ठ नागरिक (अत्याचार अपमान दुर्व्यवहार व्यवहार व दुराचार) विधेयक 2024 बनाकर पेश किया जाए जिसे सभी पार्टियां एक मत होकर 544/0 मतदान से पारित करेंगी ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। साथियों बात अगर हम प्रस्तावित कानून में माता-पिता व वरिष्ठ नागरिक (अत्याचार अपमान दुर्व्यवहार निवारण) विधेयक 2024 की जरूरत की करें तो, हमारा देश महान संतानों की भूमि है,यहां बच्चों से अपने बुजुर्ग माता-पिता की उचित देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन पीड़ादायक है कि नैतिक मूल्यों में इस कदर गिरावट आ गई है कि अपना सुख-चैन जिन बच्चों के लिए माता-पिता त्याग कर जीवन खत्म कर देते हैं, वही बच्चे उन्हें बुढ़ापे में दो जून की रोटी और मोहब्बत के लिए तरसा रहे हैं। साथियों बात अगर हम माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2019 की करें तो, प्रावधान-धारा 2 डी के तहत इन्हें मिलेगा फायदा, जन्मदाता माता-पिता, दत्तक संतान ग्रहण करने वाले, सौतेले माता और पिता-धारा 2(जी) उनके लिए जिनके बच्चे नहीं-अधिनियम की ये धारा उनके लिए है, ऐसे में उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी वे संबंधी उठाएंगे जो उनकी संपत्ति के हकदार हैं। साथियों बात अगर हम माता-पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण (संशोधित) अधिनियम 2019 को बनाने की जरूरत की करें तो, अपने ही देश,समाज और घर परिवार में बेगाने होते जा रहे बुजुर्गों की स्थिति पर उच्चतम न्यायालय ने भी चिंता व्यक्त की है।

राजनाथ और ऑपरेशन सिन्दूर

विपक्ष की भारी ना-नुकर के बाद आज लोकसभा में ऑपरेशन सिन्दूर पर चर्चा की शुरुआत रक्षामन्त्री श्री राजनाथ सिंह ने करते हुए स्पष्ट किया कि इस सैनिक अभियान में भारत ने अपना सैन्य लक्ष्य प्राप्त कर लिया था जिसकी वजह से इस पर चार दिन बाद विराम लगा दिया गया। मगर यह अभियान बन्द नहीं हुआ है, बल्कि यह चेतावनी है कि अगर पाकिस्तान ने फिर से किसी प्रकार का दुस्साहस आतंकवादी गतिविधि को लेकर किया तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। रक्षामन्त्री को भारत के उन राजनीतिज्ञों में गिना जाता है जो अवसर पड़ने पर सटीक तरीके से भारत की बात कहते हैं और दो टूक तरीके से राजनैतिक भ्रम को छांटने में माहिर माने जाते हैं। हालांकि चर्चा शुरू होने से पहले आज सदन तीन बार स्थगित हुआ और चर्चा 12 बजे के स्थान पर दोपहर बाद 2 बजे शुरू हो सकी। विपक्षी सांसद यह मांग कर रहे थे कि चर्चा इस शर्त के साथ शुरू होनी चाहिए कि बाद में सरकार बिहार में हो रहे सघन मतदाता पुनरीक्षण पर भी बहस करायेगी। सरकार ने विपक्ष की यह मांग नहीं मानी। ऑपरेशन सिन्दूर को भारत का सफल अभियान बताते हुए श्री राजनाथ सिंह ने खुलासा किया कि विगत 6 व 7 मई की अर्धरात्रि को शुरू हुए इस सैनिक ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तानाबूद कर डाला और 11 सैनिक अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान की तरफ से भी इसके विरोध में सैनिक जवाब देने की कोशिश की गई मगर भारत की तीनों सेनाओं की संयुक्त कार्रवाई ने उसके इरादों को तहस- नहस कर डाला। रक्षामन्त्री ने साफ किया कि यह ऑपरेशन भारत की सामर्थ्य और शक्ति का शानदार प्रदर्शन था जो केवल चार दिन ही चला था और उसमें घबराकर पाकिस्तान युद्ध बन्दी की याचना करने लगा। राजनाथ सिंह के अनुसार वास्तव में ऑपरेशन सिन्दूर भारत का राजनैतिक-सैनिक अभियान था जिसने अपना लक्ष्य प्राप्त किया। भारत का उद्देश्य इसे पूर्ण युद्ध में तब्दील करने का बिल्कुल नहीं था। इसी वजह से इस पर चार दिन बाद विराम लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कहीं कोई तुलना नहीं है क्योंकि भारत शान्ति का प्रणेता है मगर कोई इसे यदि उसकी कमजोरी समझता है तो भारत सैन्य मुकाबला करके अपनी शक्ति का परिचय देना भी जानता है। रक्षा मन्त्री के बयान से अब यह साफ हो गया है कि भारत ने ऑपरेशन सिन्दूर पर विराम किसी दबाव के चलते नहीं लगाया था, बल्कि पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने और अपना लक्ष्य साध लिये जाने के बाद ही लगाया था। उन्होंने कहा कि भारत बुद्ध का उपासक रहा है युद्ध का नहीं मगर उसकी अखंडता और संप्रभुता को यदि कोई चुनौती देने की हिमाकत करता है तो उसे माकूल जवाब देना भी आता है। रक्षामन्त्री ने भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों के ताजा इतिहास की पर्तों को खोलते हुए कहा कि पूर्व की सरकार ने पाक प्रायोजित आतंकवाद के मोर्चे पर बहुत ढुल-मुल रवैया अख्तियार किया था जबकि मोदी सरकार की नीति घर में घुसकर मारने की रही है। उन्होंने कहा कि आज का विपक्ष यह पूछ रहा है कि ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान भारत का कितना नुकसान हुआ जबकि उसे पूछना चाहिए था कि इस संक्षिप्त सैनिक कार्रवाई में पाकिस्तान के कितने विमान गिरे?

रक्षामन्त्री ने इस मुद्दे पर विपक्ष को बहुत चतुराई से घेरते हुए कहा कि पाकिस्तान एक असफल राष्ट्र है जिसने आतंकवाद को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बना लिया है। यह देश आतंकवाद की जरखेज जमीन बन चुका है। ऐसे देश का मुकाबला भारत से कोई किस प्रकार कर सकता है क्योंकि वहां तो आतंकवादियों के जनाजों में सैनिक अफसर व राजनीतिज्ञ तक शामिल होते हैं। इसलिए मोदी सरकार की यह नीति पूरी तरह उचित है कि वार्ता और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते हैं। श्री राजनाथ सिंह का यह कथन पूरी तरह उचित कहा जाएगा क्योंकि मोदी सरकार की पाकिस्तान को लेकर सोच रही है जो कि पिछली मनमोहन सरकार की नीति के एकदम उलट है। रक्षामन्त्री ने पाकिस्तान द्वारा भारत में की गई कुछ पुरानी आतंकवादी घटनाओं का जिक्र भी किया और सप्रमाण सिद्ध किया कि नवम्बर 2008 में मुम्बई में हुए हमले के बाद मनमोहन सरकार ने किस प्रकार केवल आठ महीने बाद ही मिस्र के शहर शर्म-अल-शेख में यह स्वीकार कर लिया था कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से ग्रसित देश है। जुलाई 2009 में भारत के तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. डा.मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमन्त्री यूसुफ रजा गिलानी के साथ हुई बातचीत के बाद यह स्वीकार किया था कि उनके देश में भी आतंकवाद की समस्या है और भारत-पाक वार्ता के बीच अब आतंकवाद नहीं आयेगा। वास्तव में शर्म-अल-शेख में एक संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ था जिसमें ऐसा कहा गया था और भारत ने पाक के बलूचिस्तान राज्य में हो रही आतंकवादी घटनाओं की जांच करने पर भी सहमति व्यक्त कर दी थी। राजनाथ सिंह ने बहुत करीने से भारत-पाक सम्बन्धों का खुलासा करने का प्रयास किया और यह जाहिर करने की कोशिश भी कि ऑपरेशन सिन्दूर में पाकिस्तानी नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया जबकि पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब आया उसमें निरीह भारतीय नागरिकों को भी निशाना बनाया गया था, खासकर सीमा पर बसे लोगों को। भारत ने तो इस ऑपरेशन का पूरा ब्यौरा संसद के पटल पर रख दिया और कहा कि केवल 22 मिनट के दौरान ही 7 मई की अर्धरात्रि को भारतीय सेनाओं ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। विगत 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाक आतंकवादियों ने जिस तरह धर्म पूछकर 26 लोगों की हत्या की थी उसका उद्देश्य भारत में साम्प्रदायिक दंगे भड़काना रहा होगा मगर भारत की महान जनता ने इस दुष्टता को पूरी तरह पहचान कर ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। भारत के समावेशी सामर्थ्य का भी यह परिचायक है।

भारतीय पासपोर्ट की बढ़ती लोकप्रियता !

हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। पिछले वर्ष के 85वें स्थान से 8 पायदान ऊपर चढ़कर भारत अब 77वें स्थान पर पहुंच गया है। इसका सीधा लाभ पासपोर्ट धारकों को मिल रहा है और यह हमारी अर्थव्यवस्था तथा वैश्विक संबंधों के लिए भी शुभ संकेत है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक वैश्विक बेंचमार्क है जो दुनिया के पासपोर्टों को उनकी यात्रा स्वतंत्रता के आधार पर रैंक करता है। यानी कोई पासपोर्ट धारक बिना पूर्व वीज़ा के कितने देशों की यात्रा कर सकता है। भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में यह सुधार सीधे तौर पर भारतीय नागरिकों के लिए अधिक वीज़ा मुक्त या वीज़ा ऑन अराइवल देशों तक पहुंच का मार्ग प्रशस्त करता है। वर्तमान में भारतीय पासपोर्ट धारक 59 देशों में बिना पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं, जबकि पिछले साल यह संख्या 57 थी। इसमें फिलीपींस और श्रीलंका जैसे नए देश भी शामिल हुए हैं। यह बढ़ी हुई पहुंच भारतीय यात्रियों के लिए कई मायनों में फायदेमंद है। वीज़ा प्रक्रिया अक्सर लंबी, जटिल और खर्चीली होती है। वीज़ा मुक्त या वीज़ा-ऑन-अराइवल की सुविधा यात्रा योजना को सरल बनाती है, समय बचाती है और अचानक यात्राओं को संभव बनाती है। यह व्यापार, पर्यटन और व्यक्तिगत यात्राओं को बढ़ावा देता है। व्यापारिक पेशेवरों के लिए आसान अंतर्राष्ट्रीय यात्रा व्यावसायिक अवसरों को बढ़ाने में मदद करती है। इससे विदेशी निवेश आकर्षित होता है और भारतीय व्यवसायों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचने में आसानी होती है। भारतीय पर्यटकों के लिए अधिक गंतव्यों तक आसान पहुंच अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को प्रोत्साहित करती है जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है। छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए, आसान यात्रा विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन या शोध के लिए नए अवसर खोलती है जिससे ज्ञान और सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ता है। एक मजबूत पासपोर्ट किसी देश की वैश्विक प्रतिष्ठा और उसके नागरिकों की स्वीकार्यता को दर्शाता है। यह भारत की बढ़ती 'सॉफ्ट पावर' का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में इस उछाल के पीछे कई कारक जिम्मेदार हैं। भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और वीज़ा समझौतों को उदार बनाने पर विशेष जोर दिया है। विदेश मंत्रालय की सक्रिय कूटनीति ने कई देशों को भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा नीतियों में ढील देने के लिए प्रेरित किया है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और वैश्विक भू-राजनीति में इसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। भारत का आर्थिक उदय और रणनीतिक महत्व अन्य देशों को भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने और भारतीय नागरिकों को अधिक सुगम यात्रा सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

सम्पादकीय...

बिन पानी के जीना दूभर

दिल्ली के मयूर विहार फेज़ 3 के बिलकुल निकट बसी खोड़ा कॉलोनी मूलतः गाजियाबाद जिले के अंतर्गत आती है। दिल्ली नोएडा गाजियाबाद के मजदूर, टेक्नीशियन, बिजली, पानी और मकान के कामगारों का ठिकाना यही खोड़ा कॉलोनी है। सबकुछ है, बस पानी नहीं है। कुछ लोग इसे एशिया की सबसे बड़ी अवैध कॉलोनी बता देते हैं। खोड़ा रेजिडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जोशी कहते हैं, - 3500-4000 टीडीएस का भू-जल है। 800-1200 फिट की गहराई पर बोरिंग करने पर पानी मिलता है। इस पानी से लोगों को लीवर की बीमारी, पीलिया, कैंसर जैसी घातक बीमारियाँ हो रही हैं। किडनी फेल हो रही है और लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। उ.प्र. के नगर विकास मंत्री से लेकर सांसद, विधायक सब बस आश्वासन देते हैं। सरकार के दफ्तर में इधर-उधर मामला लटकता रहता है। बिजली,फोन का सिस्टम नोएडा से है। सेक्टर 62 में बिजली बिल भरते हैं। लोनी, गाजियाबाद हमारा ब्लॉक है और मकान की रजिस्ट्री गाजियाबाद से होती है। कई लोगों के मकान की रजिस्ट्री नोएडा के दादरी से है। ऐसे में हमें यह भी पता नहीं, कि यह कालोनी अवैध या है क्या? हाउस टैक्स खोड़ा को देते हैं। यहाँ नगर पालिका की बिल्डिंग है, लेकिन हाउस टैक्स भी नकद लिया जाता है, चेक से आप जमा नहीं कर सकते। बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं और इलाज की सुविधा के लिए दिल्ली जाते हैं। अंतिम संस्कार गाजीपुर में हो जाता है। यहीं पर रहने वाले कवि और लेखक कमलेश कमल कहते हैं, खोड़ा का क्षेत्रफल कोई 12.5 किमी के क्षेत्र में फैला है। अब यह अवैध कालोनी नहीं है, गाजियाबाद नगर निगम के अधीन है। 34 वार्ड हैं, पार्षद चुने जाते हैं, इसके सामने नेशनल हाई-वे के दूसरी तरफ गाजियाबाद के इंदिरापुरम की अट्टालिकाएं हैं। बिल्डरों की विकसित की तमाम सोसाइटियाँ हैं, लाखों की संख्या में फ्लैट हैं। खोड़ा के एक तरफ दिल्ली एनसीआर का विकसित और योजनागत तरीके से विकसित नोएडा शहर शुरू होता है। नोएडा और गाजियाबाद के अलावा खोड़ा कालोनी दिल्ली की मयूर विहार फेज-3, न्यू कोंडली से सटा हुआ है। तीनों शहरों के घरेलू कामगार, कंपनियों में काम करने वाले लोग, दिहाड़ी मजदूर सब खोड़ा से ही निकलकर जाते हैं। खोड़ा की आबादी भी 15 लाख से अधिक है। मकानों की बात करें, तो इनकी संख्या भी 55-60 हजार के करीब होगी। 60 प्रतिशत से अधिक मकान तीन से चार मंजिला हैं। सोचिए ! 55-60 हजार मकान, बेतरतीब बसी कालोनी, पतली-पतली सड़कें, मंगल बाजार, बुद्ध बाजार समेत तमाम कालोनियों के नाम के आगे जुड़ा शब्द विहार, रहने वाले भी अधिकांश उ.प्र. और बिहार के लोग, ऐसे में मकानों का पता ढूंढना भी किसी कसरत से कम नहीं है। 2020 में पूर्व केन्द्रीय मंत्री और गाजियाबाद के सांसद वी के सिंह तथा साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा ने खोड़ा के हर मकान को नंबर आवंटित करने का वादा किया। काम शुरू हुआ। योजना है,कि 10 सेक्टर में खोड़ा को बाँटकर, गूगल मैपिंग के साथ हर मकान को एक नंबर मिल जाएगा, लेकिन कहा जाता है कि यह शुरू होता है और फिर अटक जाता है। ऐसा बसा है खोड़ा, कि किधर से शुरू करें और किसे कौन सा नंबर दें? सब तिलिस्मी खेल जैसा है। दिलचस्प है, कि खोड़ा में कुल चार सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं, इसके बाद न कोई सरकारी स्कूल है, न अस्पताल, न प्राथमिक उपचार केंद्र और न कुछ। विनय मिश्र नोएडा की एक फैक्ट्री में काम करते हैं। 35 गज के प्लाट में किसी तरह से मकान बनाया था, लेकिन पानी के लिए बेजार हैं। बताते हैं पहले 750 फीट की बोरिंग की कराई थी। अब 800 फीट से अधिक की बोरिंग हुई है, लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा है। जो पानी आ रहा है, उसका रंग लाल है, पीना तो दूर, नहाने के लायक नहीं है। सीवर की भी समस्या विकराल है। कपड़े भी नहीं साफ किए जा सकते। पहले खोड़ा की हालत बड़ी नाजुक थी। खोड़ा में सड़कें नहीं थीं। बारिश में भारी जल जमाव हो जाता था। गलियों में तार लटके रहते थे। बिजली कटौती भी खूब होती थी। छोटे-छोटे माचिस की डिब्बियों से मकान। यही खोड़ा था। अब खोड़ा में सड़कें हैं। रंग-बिरंगे, अच्छे मकान हैं। सड़क है, बिजली है, लेकिन जीवन का आधार पानी गायब। अनवर सिलाई का काम करते हैं। अनवर का भी छोटा सा 50 गज के प्लाट में मकान है। तीन मंजिला बना रखा है। मकान में बिजली है, सामने सड़क है, लेकिन साफ पानी की बूँद दूभर है। वे बताते हैं, कि 30 रुपये के हिसाब से रोज 20 ली. पानी की तीन-चार केन खरीदते हैं। इसी से खाना बनता है। हफ्ते में परिवार के लोग दो दिन ही नहा पाते हैं। सीमा यादव बुद्ध विहार में मिलीं, सीमा के पति ई-रिक्शा चलाते हैं, बेटी नोएडा की गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है और बेटा 12वीं पास हो गया है, लेकिन पानी की किल्लत ने जीना दूभर कर रखा है। मकान बेच कर वह हिंडन के किनारे छजारसी जाना चाहती हैं, लेकिन सीमा को पानी के संकट के कारण खरीददार भी नहीं मिल पा रहे हैं। एटा के संजय भी परेशान हैं, जो सेक्टर 62 से दिल्ली के पटपड़गंज, आनंद विहार तक आटो चलाते हैं। संजय की पत्नी घर में बच्चों को संभालती है, लेकिन रोज की कमाई का 22-25 प्रतिशत हिस्सा पानी में चला जाता है। रोहन बताते हैं, कि कभी टैंकर का पानी आ गया, तो पूरे महाभारत की फिल्म चलने लग जाती है, कारण बस एक है, एक टैंकर पानी आता है और एक अनार के 100 बीमार, फिर फुटौव्वल शुरू कर देते हैं। पलक झपकते ही टैंकर का पानी भी ऊंट के मुँह में जीरा की तरह खत्म हो जाता है। बताते हैं विधायक जी आए थे। वादा कर गए थे, कि गंगा नदी की पाइप लाइन आएगी। सबको पीने का साफ मिलेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी खोड़ा में पानी की आपूर्ति बड़ा मुद्दा था, लेकिन चुनाव हो गया, तो अब नेता जी भी नहीं आते। बताते हैं, इन दिनों कोई बड़ा नेता, चाहे वह केन्द्र का हो या राज्य सरकार का खोड़ा कालोनी में नहीं आना चाहता। उसे पता है, कि एक सुर में बस पानी की माँग की उठेगी। सुरेन्द्र गुप्ता ठीक-ठाक काम धंधे के सिलसिले में बलिया से आए थे। मकानों में पीओपी करते हैं। मजबूरी में लाल पानी पीना पड़ा। तीन महीने भी नहीं बीते और उनके पाचन तंत्र अब कड़ी चेतावनी दे रहा है। अनिल कुमार का कहना है कि बोरिंग का पानी खारा है, इसके अलावा कोई और पानी की पाइप लाइन नहीं है।

भूख को चित्रित करती हैं अमरकांत की कहानियां

अनीश अंकुर

बिहार प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष संतोष दीक्षित ने विषय प्रवेश कराते हुए कहा अमरकांत नई कहानी के दौर में चिह्नित किये गए। नई कहानी का दौर आज़ादी के बाद आता है। इस दौर में अचानक से हमारे सोचने का मेयार बदलने लगा। अब यूरोप से गुलाम वाला भाव नहीं था। हम अब यूरोप से अकुंठ भाव से सीखने का प्रयास कर रहे थे। स्त्री-पुरुष संबंधों की एक नई व्याख्या शुरू हुई। 1955 में अमरकांत की कहानी इंटरव्यू आई थी। अमरकांत ने सादगी और सच्चाई के साथ निम्न वर्ग के जीवन को अपनी कहानियों का विषय बनाया। गांधी जी की हत्या के बाद समाज में अनास्था फैल गई थी। अमरकांत उसी अनास्था के लेखक थे। उनकी जिन्दगी और जोंक या डिप्टी कलेक्टर कहानी पढ़ें तो आपको नये दौर का पता चलेगा। अमरकांत हमेशा प्रगतिशील तबकों के बारे में बात करते रहे। अमरकांत की कहानियों को पढ़ते हुए आँखों में आंसू आ जाते हैं। वे प्रेमचंद की परम्परा को आगे बढ़ाते रहे। हाजीपुर महिला कॉलेज में हिंदी की असिस्टेंट प्रोफेसर अनिशा ने अमरकांत की कई कहानियों का उदाहरण देते हुए बताया -रवीन्द्र कालिया ने अमरकांत की 129 कहानियों का संकलन प्रकाशित किया था। अमरकांत को प्रेमचंद की परम्परा का कहानीकार माना जाता है। यशपाल ने उनकी तुलना (मैक्सिम) गोर्की से की थी। उनकी एक कहानी में आर्थिक विपन्नता के कारण पिता काम करने के लिए बाहर जाने की बात करता है। लेखक गरीबी, भुखमरी का चित्रण तो करता ही है अमरकांत उच्च वर्ग के अंदर निम्न वर्ग के प्रति घृणा के भाव को भी सामने लाते हैं। निम्न वर्ग की समस्या खुल कर आई है अमरकांत में। एक कहानी में कहा जाता है नीच और नींबू को निचोड़ने का ही काम करना चाहिए। पलाश के फूल में स्त्री पुरुष के संबंधों को विषय बनाया गया है। अमरकांत की साधारण लगने वाली कहानी में असाधारणता लगती है। जिन्दगी और जोंक में जीवन से चिपके रहने की भावना है। मार खाकर, दुत्कारा जाकर भी जिंदगी जीने की इच्छा बनी रहती है । वैसे मुझे दोपहर का भोजन कहानी बहुत प्रिय है। सासाराम से आये चर्चित कथाकार नर्मदेश्वर ने अपने संबोधन में कहा अमरकांत जी से मैं कथापर्व समारोह में मिला था। जिस परिवेश में रहा करते थे उसी परिवेश की कहानियाँ वे लिखा करते थे। अमरकांत जी साधारण को विशिष्ट बनाने की कला में माहिर थे। दोपहर का भोजन कहानी के बारे में यशपाल ने कहा था ऐसी ठंडी और बिना घटना के कहानी लिखना सबके बूते की बात नहीं है। डिप्टी कलेक्टरी में पिता बेटा के लिए मेवा खरीद कर लाता है। अमरकांत छोटी-छोटी बातों को विस्तार देते हैं। विस्तार देने की कला जाननी हो तो डिप्टी कलेक्टर कहानी पढ़ने की जरूरत है। आलोचक कुमार सर्वेश ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कहा -अमरकांत की सूखा पत्ता उपन्यास पढ़ा तो मुझे गुनाहों का देवता की याद आती रही। भूख की समस्या पर जितना अमरकांत ने लिखा उतना बहुत कम लोगों ने लिखा है। स्त्री पात्रों में उन्होंने दिखाया कि उन्हें भूख के साथ साथ पितृसत्ता का भी बोझ है उसपर। भूख के सवाल को उन्होंने जाति के सवाल से भी जोड़ कर देखने का प्रयास किया। प्रेमचंद व अमरकांत दोनों यथार्थवादी धारा के रचनाकार हैं लेकिन प्रेमचंद मुख्यतः ग्रामीण पृष्ठभूमि के लेखक हैं वहीं अमरकांत शहरी निम्नवर्ग को केंद्र में लाते हैं। दोपहर के भोजन, जिन्दगी का जोंक आदि में हमने एक बिल्कुल नये नजरिये से देखने की कोशिश की। हमारी सरकार शहर केंद्रित विकास करने की कोशिश कर रही है। अमरकांत अपनी रचनाओं में स्त्री की आदर्शवादी नैतिकता के बजाये मध्यवर्गीय अंतर्विरोध को सामने लाते हैं। स्त्री पात्र यथार्थ के धरातल पर खड़े दिखाई देते हैं। निम्न वर्ग की समस्या खुल कर आई है। अमरकांत की प्रासंगिकता आज अधिक दिखाई पड़ता है। हम लैंगिक संदर्भ में जब भी जाते हैं वहाँ पुरुषवादी दृष्टिकोण सामने आ जाता है। चर्चित कथाकार व नाटककार हृषीकेश सुलभ ने कहा -यथार्थ को चुनना, उसे रखना और यथार्थ के गर्भ से भाषा को बरतना एक कठिन काम है। जिन लोगों को किनारा करके हम आगे बढ़ जाते हैं उन्हें कैसे कहानी में लाया जाता है इसकी कला हमें अमरकांत से सीखनी चाहिए। अमरकांत ने जो भाषा अर्जित की है वह अलग से देखने की कोशिश करेंगे तो नहीं दिखाई पड़ेगा वह भाषा कहानी के अंदर विन्यस्त रहा करती है। अमरकांत यथार्थ खोजने के लिए झोला लेकर नहीं निकलते हैं। डिप्टी कलक्टर में पिता बेटा को सिगरेट मुहैया कराता है इसके पीछे उसका लालच है। हत्यारे कहानी में लफ्फाजों को सामने लाया जाता है। पूरे तंत्र पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। मैंने सबसे पहले हत्यारे का ही नाट्य रूपांतरण किया था। भाषा और शिल्प के बजाये जीवन से चीजों को कैसे ढाला जाए इसे हमें अमरकांत से सीखा जाना चाहिए। पटना कॉलेज के पूर्व प्राचार्य और आलोचक प्रो तरुण कुमार ने बातचीत में हस्तक्षेप करते हुए कहा हत्यारे कहानी पढ़ते हुए हमें प्रेमचंद की कहानी घीसू-माधव की याद आती है। हत्यारे के पात्र भी मदिरालय जाकर रचनात्मक कार्य करने की बात करते हैं। कहानी ऐसी जगह जाकर खत्म होती है कि हमारे अंदर गूंज-अनुगूंज छोड़ देता है कि इसने हत्या की है यह दोषी है या इनका इस्तेमाल किया गया है। किसी एक कहानीकार को पढ़ते हुए यदि कोई पूर्ववर्ती रचनाकार याद आये या कौंध जाए तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। स्थितियों-परिस्थितियों को कलमबंद करना कला बड़ी बात होती है । डिप्टी कलेक्टर के शिवनाथ बाबू जैसे पात्र हिंदी कहानी में कालजयी की गिनती में आते हैं। इस कहानी में इतने किस्म की हँसी आती है कि रघुवीर सहाय की हँसो-हँसो कविता की याद आती है। अमरकांत की कहानियाँ कहीं से भी लाउड नहीं हैं, कोई चीज थोपी नहीं जाती कोई विचारधारात्मक आग्रह नहीं दिखता है। कहानी में स्थितियों को जोड़ने की जितनी कड़ियाँ और तरकीबें उन सब में माहिर से नजर आते हैं अमरकांत। उन्होंने हिंदी साहित्य को अनेक ताजे फूलों से सुशोभित किया है। प्रथम सत्र की अध्यक्षता करते हुए साहित्य अकादमी से सम्मानित कवि अरुण कमल ने कहा जब मैं पटना प्रगतिशील लेखक संघ का सचिव था तो नंदकिशोर नवल अध्यक्ष थे तब हमने अमरकांत को बुलाया था। उनके दामाद भी पटना में ही रहा करते थे। अमरकांत का पारिवारिक रिश्ता बिहार से रहा है, प्रगतिशील लेखक संघ से तो उनका जुड़ाव था ही। अमरकांत जी ने भूख का जैसा चित्रण किया है वैसा बीसवीं सदी की कहानी में बहुत कम है। तुलसी दास की विनय पत्रिका जैसा भूख का काफी जिक्र है, उतना कहीं नहीं हुआ है। भूख के जितने बिंब तुलसी दास के यहां है उतने कहीं नहीं है। अमरकांत ने जो किया वैसा किसी दूसरे ने नहीं किया है। अमरकांत में कोई जादू नहीं है बल्कि जीवन जैसा है वे उसके बारे में लिखा करते हैं। मार्केज से किसी ने पूछा कि जादुई यथार्थवाद क्या है तो उनका जवाब था यथार्थवाद का कोई विकल्प नहीं है। साहित्य ने पूरी दुनिया में यह उद्घाटित किया कि जीवन को कला में बदलना बहुत कठिन है। इसके लिए, जीवन की खोज करनी पड़ती है। जीवन का जहाँ अंतर्विरोध है उसे ढूंढना पड़ता है। अभी तरुण जी ने कई किस्म की हँसी के बारे में बताया वैसे ही अमरकांत की कहानियों में हवा चलने के इतने वर्णन हैं कि उनकी भी सूची बनाई जा सकती है। ऐसे ही उनकी कहानियों में संवाद हुआ करता है। इतने जीवंत संवाद नई कहानी के संदर्भ बात करें वे किसी के पास नहीं है। उनकी भाषा हिंदी और भोजपुरी दोनों मिली-जुली है। वैसे उनकी कुछ बातें खटकती हैं जैसे जाति को लेकर। विरासत में बहुत बातों को छोड़ना पड़ता है और कुछ को आगे भी ले जाना पड़ता है। दूसरे सत्र का विषय था कथा का समकालीन परिदृश्य और अमरकांत। इस सत्र का संचालन किया प्रगतिशील लेखक संघ के राय कार्यकारिणी सदस्य मनोजकान्त शर्मा ने। मगध विश्विद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक श्रीधर करुणानिधि ने नये कथाकारों का जिक्र करते हुए कहा समकालीन कथा परिदृश्य में तीन-तीन पीढ़ियों के लोग मौजूद हैं। कहानी के कहन के ढाँचे में बहुत कुछ गुंजाइश नहीं है। अमरकांत के यहां रोमानीपन नहीं है। उनकी हत्यारे कहानी युवाओं की दिशाहीनता को प्रदर्शित करती है। नये दौर के कथाकार अमरकांत से कितना कुछ ले सकते हैं यह हमें देखना है। सुरेन्द्र स्निग्ध कहा करते थे रेणु की नकल करना है नष्ट हो जाना। नई पीढ़ी के कहानीकारों के समक्ष दूसरे ढंग की चुनौतियां हैं। सीधी और सपाट कहानी भी अंतस्थल जो छू सकती है। कथालेखन की परम्परा कैसे आगे बढ़ती है इसे देखने की जरूरत है। हाशिये के छूट गए लोगों के जीवन को भी सामने लाना चाहिए। पटना कामर्स कॉलेज में प्राध्यापक अनिता सिंह ने कहा -अमरकांत का उपन्यास इन्हीं हथियारों से मैंने पढ़ा था। उनको पढ़ते हुए और पढ़ने की उत्कंठा बढ़ती जाती है। वे महिलाओं को कैसे देखा करते हैं इसे जिंदगी और जोंक से देखा जा सकता है। कथाकार-पत्रकार कमलेश ने भी कई कहानियों का उदाहरण देते हुए कहा अमरकांत यथार्थ को सामने रखते हैं जबकि भैरव प्रसाद गुप्त यथार्थ में बदलाव के पक्षधर रहा करते हैं। आज भूख की समस्या उनके दौर से ज्यादा गहरी है। गजा में भूख से बहुत लोग मर गए हैं। कविता ने इसको पकड़ा है, कहानी में यह बात थोड़ी कम आ पाई है। अमरकांत जी ने जिन चुनौतियों का जिक्र किया आज वे अधिक विकसित रूप में बनी हुई हैं लेकिन आज के रचनाकार उनसे ज्यादा बेहतर ढंग से निपट रहे हैं। एक इंटरव्यू में अमरकांत ने कहा था कि कहानी को समझ में आनी चाहिए तथा इसे आनंददायक भी होना चाहिए। जब आप दूसरों का दुख समझने लगते हैं तभी आप कहानी लिख पाते हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पोल्ट्रीफार्म एरिया, दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/30, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो० : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/00862)

मोती झील पर नागरिक के संघर्ष से जागी सरकार, पर ज़मीन पर कब्ज़ा जस का तस

लखनऊ।

लखनऊ की ऐतिहासिक मोती झील को संरक्षित कराने के लिए वर्षों से संघर्षरत एक पर्यावरण प्रेमी द्वारा भेजे गए विस्तृत पत्र ने प्रशासन में हलचल पैदा कर दी है। संबंधित विभाग को विधिवत भेजे गए इस पत्र में झील के सीमांकन, भू-प्राकृतिक स्वरूप, अवैध अतिक्रमण, और संरक्षण योजनाओं से जुड़ी 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। पत्र पर उनके हस्ताक्षर व सरकारी मुहर के साथ 29 जुलाई 2025 की तिथि अंकित है। इस झील की स्थिति को लेकर संबंधित विभागों को वर्षों से बार-बार जगाने वाले नागरिक सैय्यद अली हसनैन आब्दी फैज़ की सतत पहल और दबाव के चलते सरकार ने हाल ही में मोती पार्क के रूप में इस क्षेत्र के सौंदर्यीकरण की घोषणा कर दी है, जिसके लिए 7 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। यह घोषणा एक तरह से संघर्ष को शांत करने और जनआक्रोश को नियंत्रित करने का प्रयास मानी जा रही है। हालांकि यह घोषणा महज़ औपचारिक प्रतीत होती

है क्योंकि ज़मीनी सच्चाई यह है कि मोती झील की ज़मीन पर अभी भी कई स्थानों पर अवैध कब्ज़े ज्यों के त्यों बने हुए हैं, जिन पर अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस घोषणा को प्रमुख समाचार पत्रों में दबा दिया गया, ताकि व्यापक जनजागरण न हो सके। मगर सच्चाई यह है कि झील की सीमा, उसके जलग्रहण क्षेत्र, तथा कायाकल्प योजनाओं से संबंधित तमाम पहलुओं की जानकारी आम जनता से छिपाई जा रही है। पर्यावरण कार्यकर्ता सैय्यद अली हसनैन आब्दी फैज़ द्वारा पूछे गए प्रश्नों में यह स्पष्ट रूप से मांग की गई है कि झील पर किए गए किसी भी निर्माण की अनुमति किससे और कैसे मिली, इसका प्रमाण सार्वजनिक किया जाए। साथ ही यह भी पूछा गया है कि क्या झील का कोई सीमांकन किया गया है और यदि हाँ, तो उसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए। झील के लिए प्रस्तावित पुनर्जीवन योजना और

स्थल निरीक्षण रिपोर्ट जैसी जानकारियाँ भी इस पत्र में मांगी गई हैं, जो सरकार को पारदर्शिता के लिए बाध्य करती हैं। यह पूरा घटनाक्रम दर्शाता है कि कैसे एक सजग नागरिक की सतत पहल एक बड़े पर्यावरणीय मुद्दे को पुनः जनचर्चा में ले आई है। पर्यावरण प्रेमियों और शहर के जिम्मेदार नागरिकों की यह उम्मीद है कि अब केवल घोषणाओं से काम नहीं चलेगा- ज़मीनी कार्यवाही भी होनी चाहिए।

मां-बेटे पर ईंट-पत्थर से हमला, मोबाइल और नकदी लूटकर फरार हुए हमलावर

बरेली।

थाना सुभाष नगर क्षेत्र में मां के साथ कार में जा रहे एक युवक पर ईंट-पत्थरों से हमला कर मोबाइल और नकदी लूटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना सोमवार शाम की बताई जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे कुछ युवक मिलकर कार सवार को घेरते हैं और उसकी बेरहमी से पिटाई करते हैं। जानकारी के अनुसार, युवक अपनी मां के साथ कार से मुस्लिम बहुल क्षेत्र की ओर जा रहा था। आंधी पुलिया के पास मूत्र त्याग के लिए जैसे ही उसने कार रोकी और सड़क किनारे गया, वैसे ही स्थानीय लोगों का एक झुंड वहां आ धमका। युवक का आरोप है कि बिना किसी बातचीत के उसे घेरकर लात-घूंसे और ईंट-पत्थरों से पीटा गया। जेब से मोबाइल और पैसे भी ले गए, कार पर भी हमला। पीड़ित युवक ने बताया कि हमलावरों ने उसके कपड़े तक खींचे, जेब में रखे हजारों रुपये और मोबाइल फोन लूट लिए। इसके बाद कार पर भी पत्थरों की बौछार कर दी गई, जिससे कार के शीशे टूट गए। अचानक हुए हमले से युवक

वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई

और उसकी मां गहरे सदमे में हैं। घटना की जानकारी मिलते ही थाना सुभाष नगर पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मामले को संज्ञान में लिया और अज्ञात आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, और संदिग्धों के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, हमले की वास्तविक वजह का भी पता लगाया जा रहा है।

स्मार्ट हो रहे हैं परिषदीय विद्यालय, बदल रही है तस्वीर

लोधवाखेड़ा और कटरी शंकरपुर सराय दे रहे निजी स्कूलों को टक्कर

कानपुर।

अब परिषदीय विद्यालय केवल नाममात्र के शैक्षिक केंद्र नहीं रह गए हैं। आधुनिक सुविधाओं, शिक्षकों के समर्पण और नवाचारों के चलते ये स्कूल निजी संस्थानों को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। कल्याणपुर विकास खंड के उच्च प्राथमिक विद्यालय लोधवाखेड़ा और कटरी शंकरपुर सराय इसी परिवर्तन की मिसाल बनते जा रहे हैं। लोधवाखेड़ा स्थित विद्यालय में बीते तीन वर्षों से छात्र संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2023-24 में जहां 117 छात्र पंजीकृत थे, वहीं 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 122 हो गया। वर्तमान सत्र में कुल 129 विद्यार्थी नामांकित हैं। यह रुझान दर्शाता है कि अब अभिभावक पुनः परिषदीय शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा करने लगे हैं। सोमवार को सदर उपजिलाधिकारी अविचल प्रताप सिंह ने विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा संचालित इको क्लब का अवलोकन किया। दीवारों पर उकेरे गए पर्यावरण संदेश, सजे-संवरे गमले और बच्चों की सक्रिय भागीदारी देखकर उन्होंने प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि विद्यालय में पर्यावरण चेतना को जीवनशैली का हिस्सा बनाना एक प्रशंसनीय पहल है। विद्यालय में स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, वाचनालय और कंप्यूटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बच्चे दीक्षा ऐप व अन्य डिजिटल माध्यमों से अध्ययन कर रहे हैं। खेलकूद, उद्यान और स्वच्छ वातावरण ने इस स्कूल को एक आदर्श शिक्षण केंद्र में बदल दिया है। यही कारण है कि अभिभावक अब निजी विद्यालयों के बजाय इस संस्थान को प्राथमिकता देने लगे हैं। इसी क्रम में एसडीएम ने कटरी शंकरपुर सराय विद्यालय का भी दौरा किया। यह शिक्षण संस्थान अपने सुव्यवस्थित, हरे-भरे और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है। चारों ओर छायादार वृक्षों की हरियाली, आकर्षक भित्तिचित्र और संतुलित बागवानी इसे एक आदर्श परिसर का स्वरूप प्रदान करते हैं। यहां भी आधुनिक तकनीकों से युक्त कक्षाएं, पुस्तकालय और कंप्यूटर कक्ष उपलब्ध हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार सिंह ने कहा कि इन विद्यालयों ने यह प्रमाणित किया है कि जब शिक्षक समर्पण और नवाचार के साथ कार्य करते हैं तो सरकारी स्कूल विकल्प नहीं, बल्कि पहली पसंद बन जाते हैं।

बोल बम का संकल्प बन गया आखिरी सफर

हरिद्वार से लौटते समय हादसे में बड़े भाई की मौत, छोटा गंभीर घायल

बरेली।

हरिद्वार से बोल बम का संकल्प लेकर लौट रहे दो सगे भाइयों की बाइक सोमवार सुबह नजीबाबाद के पास हादसे का शिकार हो गई। डिवाइडर से टकराने के चलते बड़ा भाई मौके पर ही मौत की नींद सो गया, जबकि छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मां और पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। पटेल विहार, थाना सुभाष नगर निवासी प्रमोद ने बताया कि उनके भतीजे शोभित (30) और सौरभ (25) रविवार को हरिद्वार से जल लेने के लिए बाइक से रवाना हुए थे। सोमवार सुबह घर लौटते समय नजीबाबाद के पास नींद की झपकी आने से बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक चला रहे शोभित की मौके पर ही मौत हो गई। पीछे बैठे छोटे भाई सौरभ को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल बरेली रेफर कर दिया गया। सौरभ की हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों के मुताबिक शोभित समाचार पत्र वितरक (हाकर) का कार्य करता था। उसने बोल बम का नारा लगाते हुए हरिद्वार से जल लाकर बाबा भोलेनाथ को अर्पित करने का संकल्प लिया था। चार दिन पहले ही उसने अपनी बेटी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया था। किसी को क्या पता था कि वह उसकी जिंदगी की आखिरी खुशी होगी।

चार दिन पहले ही मनाया था बेटी का जन्मदिन

शोभित तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ा था और पूरे परिवार का मुख्य सहारा भी वही था। उसकी मौत की खबर मिलते ही मां लक्ष्मी देवी और पत्नी अर्चना बेसुध हो गईं। पूरे मोहल्ले में शोक की लहर है।

बांदा रोटी बैंक सोसाइटी ने 50 टीबी रोगियों को गोद लेकर वितरित की पोषण किटें

बांदा।

प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निःक्षय मित्र बनकर क्षय रोगियों को गोद लेकर टीबी मुक्त अभियान में सहयोगी बनकर बाँदा रोटी बैंक सोसाइटी के संरक्षक जनाब शेख़ सऊद उद जमा साहब और सह संरक्षक श्री चंद्रमौलि भारद्वाज साहब,श्री मनु बंसल जी के संरक्षण में बाँदा रोटी बैंक सोसाइटी के संगठन मंत्री श्री सुनील सक्सेना की अध्यक्षता में रिज़वान अली अध्यक्ष बाँदा रोटी बैंक के नेतृत्व में,श्री चंद्रमौलि भारद्वाज जी के सहयोग से 50 पोषण किट 50 टी0बी0 के मरीजों बच्चों, महिलाओं,बुजुर्गों को गोद लेकर सभी मरीजों को सीएमओ कार्यालय सभागार में मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री विजेन्द्र सिंह की उपस्थिति में वितरित की गई। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 विजेन्द्र सिंह ने अपने

6 माह तक लगातार प्रत्येक माह दी जाएगी टीबी मरीजों को पोषण पोटली

उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सरकार ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है लक्ष्य को पूर्ण करने के सहयोग प्रदान करने के लिए बांदा रोटी बैंक सोसाइटी के सभी पदाधिकारी/सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने 50 टीबी रोगियों को गोद लेकर उनको पोषण किट वितरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा को टीबी भले ही जानलेवा बीमारी हो लेकिन अब इसका इलाज बुखार जैसा ही है अगर खांसी बुखार ,पसीना आना,सीने में दर्द,बलगम में खून और शरीर में गांठ जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत सरकारी अस्पताल जाकर उसकी जांच कराएं और पुष्टि

होने पर नियमित इलाज लेना आरंभ कर दें ताकि बीमारी जड़ से खत्म हो जाए।मंदिरों में घंटी बजाने से अच्छा है कि गरीब, असहाय, जरूरतमंद, मरीजों की हर संभव मदद करें! क्योंकि ÷नर सेवा ही नारायण सेवा है÷।असली ईश्वर की पूजा यही है।जो आज मुझे बांदा रोटी बैंक सोसाइटी के रूप में दिखाई दी है। वहीं जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ0अजय कुमार ने बताया कि जानलेवा नहीं है अब टीबी रोग इलाज संभव है। टीवी मरीजों के लिए केंद्र और राज्य सरकार हर माह 1000/रु का पोषण अनुदान देती है 6 माह दवा खाकर टीबी की बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीबी की निशुल्क जांच और दवाइयां उपलब्ध हैं इस अभियान में संगठन भी मरीजों को पोषण किट प्रदान कर रहे हैं।जो आज रोटी बैंक सोसायटी कर रही है इसके पहले भी रोटी बैंक सोसाइटी ने 50 टीबी मरीजों को गोद लिया था यह अपने जनहित के कार्य को प्रतिदिन लगातार अंजाम दे रहे हैं हम इन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कार्यक्रम में संरक्षक शेख सऊद उद जमा साहब ने सभी मरीजों को नियमित दवा के साथ-साथ मिली हुई पोषण किट को स्वयं इस्तेमाल करने की सलाह दी। लअध्यक्ष रिजवान अली ने सभी आए हुए मरीज को संबोधित करते हुए अतिथियों सहित सभी का आभार व्यक्त किया। वहीं संगठन मंत्री सुनील सक्सेना के द्वारा मरीजों को साफ सफाई का ध्यान रखते हुए पोषण किट का इस्तेमाल करें।अपने संगठन के द्वारा की जा रही गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में बांदा रोटी बैंक सोसाइटी से संरक्षक शेख सऊद उद जमा साहब,अध्यक्ष रिज़वान अली, संगठन मंत्री सुनील सक्सेना, उपाध्यक्ष मो0 सलीम, महामंत्री मो0 अज़हर,सचिव मोहम्मद इदरीश,कार्यालय प्रभारी मोहम्मद शमीम,सोशल मीडिया प्रभारी अखूतर किरमानी, संजय ककोनिया उदघोषक, महिला उपाध्यक्ष श्रीमती तरन्नुम फ़ात्मा, महिला संगठन मंत्री प्रीती शिवहरे,महिला सोशल मीडिया प्रभारी रिचा रैकवार,राहुल अवस्थी शाखा प्रमुख क्योटरा,सदस्य अलीमुद्दीन, संतोष आनन्द,श्रीमती रामकान्ति सिंह, श्रीमती नग्गो ख़ातून, शहाना खान, नेहा ख़ातून सहित जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रदीप कुमार, जिला पीपीएम समन्वयक गणेश प्रसाद, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर विकल्प सोनी, टीबी एच बी सुबोध यादव,पीपी एस ए एजेंसी कुमारी चंदा देवी सहित टीबी हॉस्पिटल के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी गणों पर स्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन प्रसिद्ध उद्घोषक संजय काकोनिया द्वारा किया गया।

आप बिना बुलाए जाकर गले मिलते हैं, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खरगे का पीएम मोदी पर बड़ा हमला

नई दिल्ली। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की औचक पाकिस्तान यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की निंदा करते रहे हैं, लेकिन हम इधर निंदा करते हैं और आप जाकर उनकी दावत में उन्हें गले लगा लेते हैं। आप खुद ही गलती करते हैं और दूसरों को पाठ पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी पार्टी का देश के विकास में बड़ा योगदान है, लेकिन आपके पास एक भी ऐसी उपलब्धि नहीं है। आप पंडित नेहरू को बहुत कोसते हैं। सच बताइए। गृह मंत्री पहलगाम हमले से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात की समीक्षा करने गए थे और उन्होंने कहा था कि कश्मीर में सुरक्षा ट्रिपल कर दी गई है, अगर ऐसा है तो पहलगाम में आतंकी कहां से आए? उन्होंने कहा कि हमले से सिर्फ तीन दिन पहले प्रधानमंत्री ने अपना कश्मीर दौरा रद्द कर दिया था। मैंने पहले भी पूछा था, लेकिन जवाब नहीं मिला कि क्या आपके पास आतंकी हमले की सूचना थी? 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हमला हुआ, लेकिन सरकार कह रही है कि जो कुछ हमने किया, वो सही किया। राहुल गांधी ने पहलगाम हमले को लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की, लेकिन सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। खरगे ने कहा कि सरकार को बहुत अहंकार है। जवाब देने की फुर्सत नहीं है, लेकिन लोगों को गले पड़ने की फुर्सत है। 1962 में जब भारत-चीन युद्ध चल रहा था, तब चंद सांसदों की मांग पर विशेष सत्र बुलाया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने बुलाया और कहा कि देश की जनता को ये पता चलना चाहिए, लेकिन अब आप मना कर देते हैं। हमले के बाद प्रधानमंत्री बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे थे। 24 अप्रैल को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसमें भी पीएम मोदी नहीं आए और सऊदी अरब से आकर बिहार चुनाव प्रचार करने चले गए। क्या प्रधानमंत्री की यही गंभीरता है? खरगे ने कहा कि जम्मू कश्मीर के एलजी ने खुद स्वीकारा कि पहलगाम में सुरक्षा में चूक हुई। उन्होंने हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन यह सुरक्षा में चूक है और इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री को लेनी चाहिए न कि एलजी को। आप कांग्रेस को कोसते रहते हैं, लेकिन अपना भी तो कुछ बताइए, कब तक कांग्रेस के नाम पर निंदा रहेंगे। एलजी ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली तो क्या ये गृह मंत्री को बचाने के लिए दिया गया। या एलजी को ऐसा करने के लिए दिया गया? खरगे ने आगे कहा, पहलगाम हमले के बाद सभी ने सेना को समर्थन दिया। हमने कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में फैसला किया कि ये राजनीति करने का समय नहीं है और एकजुटता दिखाने का समय है। हमने सरकार को समर्थन दिया। देशहित में हमने हर कदम पर सरकार को सपोर्ट किया, लेकिन प्रधानमंत्री विपक्षी पार्टियों के खिलाफ चुनावी भाषण करते फिरते हैं। सिर्फ चार दिनों में पाकिस्तानी फायरिंग में 27 भारतीय नागरिक, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं और 70 घायल हो गए इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भिजवाया जा सकता था, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया वरना इन्हें बचाया जा सकता था। उसके बाद भाजपा के एक राज्यसभा सांसद ने कहा कि पहलगाम हमले में जो लोग मारे गए, उनकी पत्नियों में वीरांगनाओं में जैसा भाव नहीं था, इसलिए वो हाथ जोड़ रहीं थी और गिड़गिड़ा रही थी। आपको महिलाओं के प्रति ये इज्जत है। ऐसे लोगों को कान पकड़कर बाहर निकालें। इससे बदनामी होती है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की महिला अधिकारी के बारे में मध्य प्रदेश के एक नेता की अपमानजनक टिप्पणी पर खरगे ने कहा कि ऐसे बयानों की निंदा करनी चाहिए। जब तक आप अपने लोगों को कंट्रोल नहीं करते तो दूसरी तरफ से भी प्रतिक्रिया आती है तो ये लोग देशद्रोही करार देते हैं। जैसे देशभक्ति का ठेका सिर्फ इनके पास है। सुप्रीम कोर्ट ने उस मंत्री के बयान की निंदा की, क्या भाजपा ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर निकालेंगे।

खरगे ने राज्यसभा में कहा, सरकार का कहना है कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे और पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन फिर अचानक से युद्धविराम की घोषणा हो गई। सवाल ये है कि सीजफायर की घोषणा कहां से हुई और क्यों हुई। इसकी घोषणा हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या विदेश मंत्री ने नहीं की, बल्कि अमेरिका के वाशिंगटन से हुई।

गृहमंत्री बताएं 3 आतंकी मारे गए, बाकी कहां हैं : खड़गे

नई दिल्ली।

राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है। विपक्ष की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी सरकार जब से आई है। तब से 5 बार पहलगाम में ही अटैक हुआ है। सबक सीखना चाहिए। गलती सुधारनी चाहिए, आपने क्या किया। गृहमंत्री अमित शाह बताएं इसके लिए कौन जिम्मेदार है, वह कुर्सी खाली करें। अगर कोई नहीं है तो पीएम जवाब दें। पहलगाम हमले के 100 दिन बाद भी आतंकी नहीं मिले, 3 मारे गए तो बाकी कहां हैं? उनको भी ढूंढा क्यों नहीं। 14 जुलाई 2025 को एलजी मनोज सिन्हा ने कहा था कि पहलगाम हमला सिक्योरिटी फैलियर के कारण हुआ था।

खड़गे बोले- मोदी जी इवेंटबाजी से काम नहीं चलता

मैं अब सीधे-सीधे दो चार प्रश्न पूछूंगा तो उम्मीद करता हूं जवाब देंगे। किन शर्तों पर ये सीजफायर हुआ। आपने इसे क्यों स्वीकार किया। क्या यूएस ने इसमें हस्तक्षेप किया अगर हां तो क्यों और किसके कहने पर किया। क्या यूएस प्रेसिडेंट ने यह सीजफायर किया जैसा वो बार-बार कह रहे हैं, अगर हां तो क्या यह भारत की तीसरी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ नहीं है? विदेश मंत्री तो चले गए लेकिन मैं रक्षामंत्री को सुनाना चाहता हूं कि पहलगाम के बाद मोदी जी का यह सच सामने आ गया कि इवेंटबाजी से काम नहीं चलता। जिनको आप विश्व गुरु मानते हैं। इंदिरा, नेहरू से तुलना होती है। ट्रम्प से दोस्ती है। इसलिए हमारे चेयरमैन साहब चले गए। फॉरेन पॉलिसी का सच सामने आ गया। इवेंटबाजी बंद करो।

खड़गे बोले- ट्रम्प ने बार-बार कहा उन्होंने युद्ध रुकवाया

अब मैं सीजफायर पर कहूंगा कि पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। हम फटेफुट पर थे, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे... ऐसा आपका कहना है। जब सरकार की तरफ से बयान आता है तो हम समझते हैं कि सच सही होगा। फिर युद्ध विराम की घोषणा हुई। यह पीएम, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री ने नहीं की, बल्कि अमेरिकी

ट्रम्प 29 बार सीजफायर कराने का दावा कर चुके, मोदी चुप क्यों हैं

प्रेसिडेंट ट्रम्प ने की। उन्होंने दावा किया कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया। सभी ने सुना। इसके बाद भी ऐसा हो रहा है कि मानने तैयार नहीं हैं। ट्रम्प एक या दो बार नहीं 29 बार यही बात दोहरा चुके हैं। मेरा भाषण खत्म होने तक 30 हो जाएगा। उन्होंने बार बार यही कहा कि ट्रेड की शर्त पर यह युद्धविराम किया। कौन है जो महाशय जो देश बेचना चाहता है। और कौन है ऐसा देशभक्त, अडाणी के पीछे कौन है...बार बार यह भी कहा कि उन्होंने ट्रेड का इस्तेमाल कर युद्ध रुकवाया।

सरकार के भीतर सभी नंबर 1 और 2 से डरते हैं- खरगे

खरगे ने पहलगाम हमले को लेकर सवाल उठाया कि आखिर आतंकी वहां तक पहुंचे कैसे? क्या यह गृह मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के भीतर सभी नंबर 1 और 2 से डरते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी ली, लेकिन क्या यह गृह मंत्री को बचाने की रणनीति थी? जब सुरक्षा व्यवस्था विफल रही तो जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की जा रही? कांग्रेस नेता खरगे ने कहा कि उन्हें सेना पर गर्व है और उन्होंने सेना की बहादुरी को सलाम किया, लेकिन सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, ये पहाड़ खोदकर चूहा निकालने वाले हैं, साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि तीन आतंकी मारे गए, लेकिन बाकी कहां छिपे हैं? विपक्ष की चिट्ठियों को कूड़े में फेंक दिया जाता है, और जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई तो प्रधानमंत्री उसमें शामिल तक नहीं हुए.

एसआईआर के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, 12-13 अगस्त को तय हुई तारीख

बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई तो हम हस्तक्षेप करेंगे, एसआईआर पर बोला सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और वह कानून के अनुसार कार्य करने वाला माना जाता है, लेकिन अगर बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में बड़े पैमाने पर लोगों के नाम छूटे हैं, तो अदालत हस्तक्षेप करेगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बिहार में चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने के लिए समयसीमा तय की और कहा कि इस मुद्दे पर सुनवाई 12 और 13 अगस्त को होगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने एक बार फिर आरोप लगाया कि अगस्त में प्रकाशित होने वाली मसौदा सूची से लोगों को बाहर रखा जा रहा है। चुनाव आयोग द्वारा 1 नंबर पर मतदान करने से वे अपना महत्वपूर्ण मतदान का अधिकार खो देंगे। भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग ने एक बयान जारी किया है कि 65 लाख लोगों ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान गणना फॉर्म जमा नहीं किए हैं क्योंकि वे या तो मर चुके हैं या स्थायी रूप से कहीं और चले गए हैं। उन्होंने दलील दी कि इन लोगों को सूची में शामिल होने के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, भारत का चुनाव आयोग, एक संवैधानिक प्राधिकारी होने के नाते, कानून के अनुसार कार्य करने वाला माना जाता है। यदि कोई गड़बड़ी हुई है, तो आप अदालत के संज्ञान में लाएं। हम आपकी बात सुनेंगे। न्यायमूर्ति बागची ने भूषण से कहा, आपकी आशंका है कि 65 लाख से ज्यादा मतदाता मसौदा सूची में शामिल नहीं होंगे। अब चुनाव आयोग मतदाता सूची में सुधार की मांग कर रहा है। हम एक न्यायिक प्राधिकारी के रूप में इस प्रक्रिया की समीक्षा कर रहे हैं। यदि बड़े पैमाने पर लोगों को सूची से बाहर रखा जाता है, तो हम तुरंत हस्तक्षेप करेंगे। आप 15 ऐसे लोगों को सामने लाएं जिनके बारे में वे कहते हैं कि वे मृत हैं, जबकि वे जीवित हैं।

देवघर बस हादसा: 18 कांवड़ियों की मौत

देवघर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के देवघर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे पर दुख जताया है। मंगलवार को देवघर में कांवड़ियों को ले जा रही बस हादसे का शिकार हुई, जिसमें 18 श्रद्धालुओं की जान चली गई, जबकि 20 से अधिक घायल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से यह जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर की दुर्घटना पर कहा, झारखंड के देवघर में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मेरी गहरी शोक-संवेदनाएं।

ईश्वर उन्हें इस पीड़ा को सहने की शक्ति दे।

इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इसके पहले झारखंड राज्यपाल संतोष गंगवार ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देवघर से बासुकीनाथ जा रही कांवड़ियों की बस दुर्घटना में कई श्रद्धालुओं के निधन का समाचार अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है। मैं शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं तथा बाबा भोलेनाथ से घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूंराज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि आज सुबह देवघर के मोहनपुर प्रखंड के जर्मुनिया चौक के पास बस दुर्घटना में बस सवार श्रद्धालुओं की मृत्यु की अत्यंत दुखद सूचना मिली है।

जिला प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य के साथ घायलों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। बाबा बैद्यनाथ दुर्घटना में मरने वाले श्रद्धालुओं की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे।

ऐसा लगा जैसे कराची-लाहौर हमारा हो गया: संसद में अखिलेश ने कसा तंज, सुरक्षा चूक पर उठाए सवाल

नईदिल्ली। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि सरकार को युद्धविराम की घोषणा करनी पड़ी? उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि हमें तो उम्मीद थी कि सरकार खुद ही इसकी घोषणा कर देगी। लेकिन चूंकि उनकी गहरी दोस्ती है, इसलिए सरकार ने अपने दोस्त से ही युद्धविराम की घोषणा करने को कहा। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार जो दावा करती है कि जम्मू-कश्मीर में अनुछेद 370 हटने के बाद कोई आतंकवादी घटना नहीं होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि आज जब हम संसद में यह चर्चा कर रहे हैं तो सरकार को बताना चाहिए कि देश का कुल क्षेत्रफल कितना है। यादव ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा

गुठभेड़ कल ही क्यों हुई? ऑपरेशन महादेव पर अखिलेश ने उठाए सवाल, चीन को बताया राक्षस

चाले दिन ही कश्मीर में ऑपरेशन महादेव संचालित होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुठभेड़ कल ही क्यों हुई। सपा सांसद ने कहा कि यह बात पक्ष विपक्ष की नहीं है, देश की सुरक्षा, जनता के जीवन की है। पहलगाम की घटना ने साबित कर दिया है कि लापरवाही देशवासियों की जान ले सकती है। भी आतंकवादी घटना नहीं होगी। आखिरकार यह सिक्योरिटी लैपा की जिम्मेदारी कौन लेगा? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भारत को विदेश नीति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और चीन को एक राक्षस बताया जो हमारी जमीन और बाजार को हड़प लेगा। यादव ने कहा कि पहलगाम हमले में हुई खुफिया चूक की जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्होंने आगे कहा कि यह दुखद घटना कभी नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इस चूक ने कई अरमोल जानें ली है और देश की सीमा रणनीति की कमजोरियों को उजागर किया है। उन्होंने कहा, पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू करना सरकार की खुफिया विफलता का प्रतीक है।

राहुल गांधी का बड़ा फैसला! पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी में अनाथ हुए 22 बच्चों को लेंगे गोद

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक मानवीय कदम उठाते हुए पाकिस्तान की ओर से पुंछ में हुई गोलीबारी में अनाथ हुए 22 बच्चों को गोद लेंगे। यह जानकारी कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों से सामने आई है। राहुल गांधी ने मई माह में पुंछ का दौरा किया था, जहां उन्होंने स्थानीय पार्टी नेताओं से मुलाकात की और उनसे प्रभावित बच्चों की सूची तैयार करने को कहा था। इसके बाद एक विस्तृत सर्वेक्षण किया गया और सरकारी सिफारिश की जांच के बाद 22 बच्चों के नामों को अंतिम रूप दिया गया। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने क्राइस्ट पब्लिक स्कूल का दौरा किया था, जहां उन्होंने गोलीबारी में मारे गए 12 वर्षीय जुड़वां बच्चों उसबा फातिमा और जैन अली के सहपाठियों से मुलाकात की थी। पुंछ उन इलाकों में शामिल है, जो पाकिस्तानी गोलीबारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इस गोलीबारी में कई नागरिक घायल हुए थे, जिनमें बच्चे भी शामिल थे।

गृह मंत्री मेरी मां के आंसुओं तक चले गए, लेकिन यह नहीं बताया कि युद्धविराम हुआ क्यों? प्रियंका का सरकार पर तंज

नई दिल्ली। ऑपरेशन सिन्दूर पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कल रक्षा मंत्री ने एक घंटे तक भाषण दिया, आतंकवाद पर बात की, देश की रक्षा की बात की, इतिहास का पाठ भी पढ़ाया, लेकिन एक बात छूट गई - ये हमला कैसे हुआ? उन्होंने आरोप लगाया कि पहलगाम में सरकार ने लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया।

उन्होंने कहा कि मैं उन सभी जवानों को नमन करना चाहती हूं जो हमारे देश के रेगिस्तानों में, घने जंगलों में, बर्फीली पहाड़ियों में... हमारे देश की रक्षा करते हैं। जो हर पल देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि 1948 से लेकर अब तक- जब पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर पर हमला किया गया- हमारे देश की अखंडता की रक्षा करने में हमारे जवानों का बड़ा योगदान है। उन्होंने सवाल किया कि वहां (बैसरन घाटी, पहलगाम) एक भी सुरक्षाकर्मी क्यों मौजूद नहीं था? क्या नागरिकों की सुरक्षा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? उन्होंने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने आज नेहरू और इंदिरा गांधी के किए पर बात की। उन्होंने मेरी मां के आंसुओं का भी जिक्र किया। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि युद्धविराम की घोषणा क्यों की गई। प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने आज मेरी मां के आंसुओं के बारे में बात की। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। मेरी मां के आंसू तब गिरे, जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे सिर्फ 44 साल की थीं। आज जब मैं उन 26 लोगों (पहलगाम हमले के पीड़ितों) के बारे में बात करता हूं तो इसलिए कि मैं उनका दर्द समझती हूं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हमेशा सवालों से बचने की कोशिश करती है... देश के नागरिकों के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। सच तो यह है कि उनके दिल में जनता के लिए कोई जगह नहीं है। उनके लिए सब कुछ राजनीति है, प्रचार है। वायनाड से सांसद ने कहा कि आज इस सदन में बैठे जवाहरलाल लोगों को सुरक्षा कवच मिला हुआ है। लेकिन उस दिन पहलगाम में 26 लोगों को उनके परिवारों के सामने मार दिया गया था। उस दिन बैसरन घाटी में जितने भी लोग मौजूद थे, उनके पास कोई सुरक्षा नहीं थी। आप चाहे कितने भी ऑपरेशन चला लें, सच्चाई के पीछे नहीं छिप सकते। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने कहा- मैंने अपनी दुनिया को अपनी आंखों के सामने खत्म होते देखा, वहां एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। मैं ये कह सकती हूं कि सरकार ने हमें वहां अनाथ छोड़ दिया था। सवाल है कि वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, एक भी जवान क्यों नहीं था? क्या सरकार को मालूम नहीं था- वहां हर दिन 1000-1500 पर्यटक जाते हैं, वहां पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है, वहां कोई चिकित्सा का इंतजाम तक नहीं था। लोग वहां इस सरकार के भरोसे गए और सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया।

मराठा समुदाय के साथ सरकार ने किया धोखा, 29 अगस्त से फिर से अनशन पर बैठेंगे मनोज जरांगे

मुंबई। आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए मराठा समुदाय से किए गए अपने वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। जालना जिले के अंतरवाली सरथी गांव में मीडिया से बात करते हुए, जरांगे ने गहरी निराशा व्यक्त की और आरोप लगाया कि सरकार ने मराठा समुदाय के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो वे 29 अगस्त से मुंबई में फिर से भूख हड़ताल शुरू करेंगे। अतीत में कई भूख हड़तालों का नेतृत्व कर चुके जरांगे ने लगातार मांग की है कि सभी मराठों को आधिकारिक तौर पर कुनबी के रूप में मान्यता दी जाए एक कृषि प्रधान जाति जो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में आती है। उन्होंने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की भी मांग की है। उन्होंने लगातार ऐतिहासिक अभिलेखों को लागू करने की मांग की है, जिनमें बॉम्बे, सतारा और हैदराबाद के राजपत्र शामिल हैं, जिनके बारे में उनका दावा है कि ये मराठा समुदाय को कुनबी के रूप में वर्गीकृत करते हैं। जरांगे ने कहा, मराठों की चार प्रमुख मांगें, जिनके लागू होने का सरकार ने आश्वासन दिया था, पूरी नहीं हुई हैं। सरकार ने एक बार फिर समुदाय को धोखा दिया है। उन्होंने 29 अगस्त को मुंबई में फिर से भूख हड़ताल करने और शहर तक मार्च निकालने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, हम पिछले दो सालों से पैर रख रहे हैं। अब उठ खड़े होने का समय आ गया है। मैं सभी मराठियों से अपील करता हूं - चुप न बैठें। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। उन्होंने समुदाय के सदस्यों से दो महीने में अपनी खेती-बाड़ी का काम समेटकर मुंबई तक मार्च निकालने की तैयारी करने का आग्रह किया।

विधेयक को मंजूरी मामले में 19 अगस्त से सुनवाई होगी; 12 अगस्त तक सरकारों को देना है जवाब

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के संदर्भ वाले मुकदमे में आज सुनवाई की। अदालत ने समय-सारिणी तय की है। इसमें यह पूछा गया है कि विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी देने में समय-सीमा निर्धारित की जा सकती है या नहीं? राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा संसद या विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि 19 अगस्त से सुनवाई शुरू होगी। अदालत दलीलें सुनना शुरू करेगी। इससे पहले केंद्र और राज्य सरकारों को 12 अगस्त तक लिखित रूप में अपना पक्ष अदालत के समक्ष दाखिल करना होगा।

पहलगाम हमले के तीनो आतंकी ढेर - अमित शाह

नई दिल्ली।

तीन महीने ट्रैक किया, फिर घेरकर मारा; आतंकियों के पाकिस्तानी होने के 3 सबूत भी बताए

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में ऑपरेशन महादेव लेकर बड़ा बयान दिया है। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि, कल ऑपरेशन महादेव में बैसरन घाटी में 26 भारतीय पर्यटकों की हत्या में शामिल आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इस ऑपरेशन में मारे गए आतंकियों के नाम सुलेमान, फैजल अफगान और जिब्रान हैं। सुलेमान लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर था और उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। फैजल अफगान और जिब्रान दोनों ए-श्रेणी के वांछित आतंकी थे। उन्होंने बताया कि ये तीनों पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे, जिसमें निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया गया था। सुरक्षा बलों की सटीक कार्रवाई में तीनों को ढेर कर दिया गया। इसके अलावा, अमित शाह ने यह भी बताया कि आतंकियों की मदद करने वाले 2 सहयोगियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकी हमले का बदला ले लिया है। गृह मंत्री ने बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ

और सेना ने मिलकर यह ऑपरेशन अंजाम दिया। आतंकियों के पास से 3 राइफलें, जिनमें दो एके-47 और एक अमेरिकी एम9 कार्बाइन बरामद की गईं। अमित शाह ने बताया कि आतंकियों की पहचान और उनके पहलगाम हमले से जुड़ाव की पुष्टि वैज्ञानिक साक्ष्यों के जरिए की गई। पहलगाम हमले के बाद मौके से जो राइफल के खोखे बरामद किए गए थे, उन्हें चंडीगढ़ स्थित एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल जांच में यह पुष्टि हुई कि ऑपरेशन महादेव के दौरान जिन हथियारों को बरामद किया गया था, वे वही हैं जिनसे पहलगाम अटैक को अंजाम दिया गया था।

राइफल की नली और खोखों का मैचिंग टेस्ट पूरी तरह मेल खाता है, जिससे यह साबित होता है कि मारे गए आतंकी ही इस बर्बर हमले के दोषी थे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने सोमवार को संयुक्त रूप से ऑपरेशन महादेव चलाया।

आतंकियों की मदद करने वाले 2 सहयोगियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर अडिग है और देश की एकता और नागरिकों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई सुरक्षा बलों की सटीक योजना, तकनीकी दक्षता और आतंक के खिलाफ ठोस इरादों का प्रतीक है, जिसने आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। वहीं इस दौरान अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की भी बात की। उन्होंने कहा कि, जिस दिन लश्कर और टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली थी, उसी दिन से राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जांच के आदेश दे दिए थे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष, खासकर कांग्रेस और पूर्व गृहमंत्री पी. चिदंबरम पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, मारे गए आतंकियों के पास से पाकिस्तान का वोटर नंबर, राशन कार्ड और यहां तक कि पाकिस्तानी चॉकलेट तक बरामद हुए हैं। सभी सबूत हमारे पास मौजूद हैं। फिर भी पूर्व गृहमंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं?